



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1273]

No. 1273]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2005/अग्रहायण 16, 1927

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2005/AGRAHAYANA 16, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1727(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं अथवा नहीं, एतद्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जे. पी. सिंह की अध्यक्षता में एक "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है।

[फा. सं. 11011/46/2005-एन ई III]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव (एन. ई.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2005

S.O. 1727(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice J. P. Singh, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the Meitei Extremist Organisations of Manipur, as unlawful associations.

[F. No. 11011/46/2005-NE. III]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy. (N.E.)